

एलयू में कार्यपरिषद की आपात बैठक आज, संबद्धता मामलों पर लगेगी मुहर

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विवि में बुधवार को कार्य परिषद की आपात बैठक होगी। इसमें 25 कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अस्थायी सहयुक्तता एक साल के लिए बढ़ाने और पांच कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों को मान्यता देने पर फैसला होगा। इसके साथ ही चार कॉलेजों पर अर्धदंड तथा एक कॉलेज में संचालित पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त करने के साथ ही नौ कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रमों की स्थायी मान्यता पर भी मुहर लगाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तहत तीन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के संचालन पर भी कार्य परिषद फैसला करेगा। ललिवि में विभिन्न कॉलेजों को मान्यता देने

25 कॉलेजों में अस्थायी सहयुक्तता और पांच नए कॉलेजों के पाठ्यक्रमों पर होगा फैसला

इन कॉलेजों के पाठ्यक्रमों पर स्थायी मुहर का प्रस्ताव

■ गुरुनानक गल्स डिग्री कॉलेज : एमए गृहविज्ञान, एमकॉम वाणिज्य व व्यवहारिक अर्थशास्त्र, एमए शिक्षाशास्त्र ■ बलरामकृष्ण एकेडमी : बीए, बीकॉम, ■ नवदेश्वर डिग्री कॉलेज : बीकॉम, बीबीए ■ रजत युमैस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट : एमएड ■ रजत पीजी कॉलेज : एमपीएड, एमए शिक्षाशास्त्र, एमए गृहविज्ञान, एमएससी वनस्पति विज्ञान 6. राम दुलारी आलोक कुमार महिला डिग्री कॉलेज : बीए ■ महामाया राजकीय महाविद्यालय : बीएससीए ■ श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन महाविद्यालय : एमए समाजशास्त्र, एमकॉम वाणिज्य ■ इरम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल : बीयूएमएस

इन कॉलेजों में पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों पर होगा फैसला :

■ मुमताज पीजी कॉलेज : बीएससी ■ अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज : बीए, बीकॉम ■ बीएसएनबी पीजी कॉलेज, बीकॉम

कॉलेज में पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त किए जाने का प्रस्ताव :

■ बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज : एमकॉम

इन कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव

■ चंद्रभानुगुप्त कृषि महाविद्यालय, बीएससी ■ कालीचरण पीजी कॉलेज : बीजेएमसी ■ हीरालाल यादव मेमोरियल ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन : बीए ■ राम भरोसे मेकुलाल महाविद्यालय : बीए बीकॉम ■ श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशन स्टडीज : बीए

अर्धदंड के साथ चार कॉलेजों के पाठ्यक्रमों की मान्यता पर होगा विचार

■ द स्टडी हॉल कॉलेज : बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ■ लखनऊ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन : बीबीए ■ सरदार भगत सिंह कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन : बीए ■ स्वतंत्र गल्स डिग्री कॉलेज : बीए

की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित है। इसके लिए 15 मई तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी जाती है। कोरोना संकट की वजह से शासन ने मान्यता की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जो बुधवार को समाप्त हो रही है। इसको देखते हुए ललिवि ने शाम पांच बजे कार्य परिषद की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में

मान्यता संबंधी मामलों को रखा जाएगा। इसमें स्थायी मान्यता देने के साथ ही नये पाठ्यक्रम के साथ अर्धदंड तथा मान्यता समाप्ति तक के प्रस्ताव शामिल हैं। नियमों के अनुसार तीन साल तक पाठ्यक्रमों की अस्थायी मान्यता दी जाती है। इसके बाद स्थायीकरण कराना होता है। इसके लिए एक साल का मौका मिलता है।

चौथे साल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति होती है। पांचवें साल स्थायीकरण न होने पर एक लाख रुपये, छठे साल दो लाख रुपये तथा सातवें साल तीन लाख रुपये अर्धदंड के साथ पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होती है। इसके बाद स्थायीकरण न होने पर पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

ललिवि के पाठ्यक्रम में शामिल होगा कोविड-19

लखनऊ। लखनऊ विवि में नए सत्र से कोविड-19 के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ललिवि में मंगलवार को हुई विज्ञान संकाय की फैकल्टी बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। विवि में बायोकेमिस्ट्री विभाग में कोविड-19 को एक टॉपिक के रूप में शामिल किया जाएगा। फैकल्टी बोर्ड की बैठक में विभिन्न संकायों में हुए सिलेबस के बदलाव तथा शोधार्थियों के गाइड से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।

आवेदन की तिथि फिर बढ़ने की संभावना

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक, प्रबंधन, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बुधवार को समाप्त हो रही है,

लेकिन इस बार केंद्रीयकृत दाखिला प्रक्रिया के चलते विवि प्रशासन फिर से अपनी आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

विवि में इस साल स्नातक और परास्नातक के रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आ चुके हैं। स्नातक की साढ़े तीन हजार और परास्नातक की करीब साढ़े चार हजार सीट के लिए आवेदन मांगे हैं। स्नातक और परास्नातक के सभी पाठ्यक्रमों के दाखिले ललिवि करेगा जबकि बीटेक तथा एमबीए के दाखिले राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिए जाएंगे। ललिवि ने केंद्रीयकृत दाखिले से इस साल 54 कॉलेजों को भी जुड़े हैं।



■ मेरिट या प्रवेश परीक्षा से दाखिले पर अभी स्थिति साफ नहीं : ललिवि में अभी तक प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले होते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से विवि की परीक्षा फंसी हुई है। ऐसे में प्रवेश परीक्षा कराना भी एक बड़ी चुनौती है। स्नातक और परास्नातक में कुल मिलाकर 50 हजार से ज्यादा प्रवेश परीक्षार्थी हो सकते हैं। इनकी संख्या को देखते हुए विवि मेरिट से दाखिले के विकल्प पर विचार कर

रहा है। हालांकि अभी तक विवि ने इस पर अपनी स्थिति साफ नहीं की है।

■ सभी कॉलेजों में जारी है आवेदन प्रक्रिया : ललिवि के साथ ही सभी सहयुक्त कॉलेज में स्नातक और परास्नातक की आवेदन प्रक्रिया जारी है। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट न घोषित होने की वजह से आवेदन की रफ्तार काफी सुस्त है। अब सभी बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसलिए आवेदन की गति में भी तेजी आने की उम्मीद है।

31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं छात्र-छात्राएं

ललिवि

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 में स्नातक-परास्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी है। अब 15 की जगह 31 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे।

आवेदनों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल और केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

66 कॉलेज प्रवेश के लिए जुड़े

दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रही केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था को कॉलेजों के स्तर पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने इस बाबत बताया कि अभी तक करीब 66 कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने बताया कि यह संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है।



आवेदनों में रिकॉर्ड उछाल

इस बार ललिवि में प्रवेश आसान नहीं होगा। पिछले वर्षों के मुकाबले आवेदनों की संख्या में उछाल आया है। स्नातक की करीब 3500 सीट के लिए 40 हजार से ज्यादा ने पंजीकरण कराया है। परास्नातक की करीब 4500 सीट के लिए पंजीकरण 19 हजार से ज्यादा है। वहीं बीपीएड, एमपीएड, बीएड और एमएड में कॉलेज व्यक्तिगत स्तर पर प्रवेश नहीं ले सकेंगे। कुलपति ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों की नियामक संस्था एनसीईटी के नियमानुसार केन्द्रीकृत प्रवेश अनिवार्य है। जरूरी नहीं है कि यह कॉलेज ललिवि की केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था से जुड़े लेकिन केन्द्रीकृत प्रवेश लेने होंगे।

Institute of Wildlife to carry out sarus census

Lucknow (PNS): The Institute of Wildlife, Lucknow University, under a project of the Forest department, will carry out a sarus census in the state and also prepare a sarus atlas. Giving this information, coordinator of the institute Amita Kanaujia said the sarus atlas would be prepared on GPS data.

She said census would be carried out in the month of August this year. "We have charted out 15 divisions and all the 58 districts coming under these divisions will be covered," she said. She added that before the census was carried out, they would be organising a state-level workshop for the

forest personnel of UP from July 17 to 31 for the preparation of the sarus atlas.

The online workshop will be inaugurated by the Vice-Chancellor of Lucknow University and PCCE, Forest. The objectives of sponsoring the training workshop are to upgrade knowledge and skills of the forest personnel and provide maximum possible inputs on the topics and themes, including emerging trends at national and global levels. The aim is to elicit suggestions through brainstorming sessions and sharing of experiences which could be useful in policy formulation by the government.